तालुक भूमि बोर्ड और अन्य

बनाम

सिरियाक थॉमस और अन्य

10 सितंबर 2002

[सैयद शाह मोहम्मद कादरी और एस. एन. वरियावा, जे.जे.]

केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1964:

भूमि सीमा पूर्ववर्ती त्रावणकोर कोचीन राज्य में एक ईसाई की मृत्यु 1958 में अपने पीछे बेटे और बेटियों को छोड़ते हुए हुई-राजस्व अधिकारियों द्वारा घोषित बेटे के स्वामित्व में अपनी बेटियों द्वारा बेची गई भूमि और अधिशेष के रूप में घोषित कुछ भूमि-आयोजित, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम को त्रावणकोर कोचीन राज्य में विस्तारित किया गया है, मृतक के सभी बच्चों को इसके तहत भूमि विरासत में मिली है-तदनुसार, अपनी हिस्सेदारी की बेटियों द्वारा निष्पादित भूमि के बिक्री विलेख वैध थे-इसलिए, कवर की गई भूमि को घोषित बेटे के स्वामित्व में नहीं जोड़ा जा सकता था-भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925-उत्तराधिकार-भाग-बी राज्य (कानून) अधिनियम,1951

मैरी रॉय और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य [1986] 2 एस सी सी 209 पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 333-334 /1998

सीआरपी संख्या 1669-1993 और 2453/93 में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 18.11.1996 से।

अपीलार्थी के लिए श्री के. आर. शशिप्रभु के लिए जॉन मैथ्यू।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया था-

केरल भूमि सुधार अधिनियम (संक्षेप में, 'अधिनियम') के तहत गठित तालुक भूमि बोर्ड, 1993 के सीआरपी संख्या 1669 और 2453 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए सामान्य आदेश के खिलाफ अपील में है। 18 नवम्बर 1996 को, आक्षेपित द्वारा आदेश में, उच्च न्यायालय ने घोषणाकर्ता-साइरिएक थॉमस (प्रथम प्रतिवादी) की बहनों द्वारा निष्पादित बिक्री कार्यों को स्वीकार कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप उनके द्वारा आत्मसमर्पण करने के लिए कोई अतिरिक्त भूमि नहीं बची। विचार के लिए मुद्दा यह उठता है कि क्या घोषणाकर्ता की बहनों के पास स्वामित्व था भूमि या यह वास्तव में, घोषणाकर्ता की थी और इसलिए, बिक्री को नजरअंदाज किया जाना चाहिए और भूमि को उसकी हिस्सेदारी में जोड़ दिया जाना चाहिए।

एक श्री एलनजिक्कल सिरिएक की 1958 से कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। उनके परिवार में घोषणाकर्ता सहित उनके तीन बेटे और चार बेटियाँ थीं। उन्होंने कुछ कृषि भूमि छोड़ दी। 1978 में बहुत समय पहले, अपीलकर्ता ने माना था कि घोषणाकर्ता के पास आत्मसमर्पण करने के लिए कोई अतिरिक्त भूमि नहीं थी, हालाँकि, 1980 में, मामला फिर से खोला

गया और उसके द्वारा दायर आपत्तियों पर विचार करने के बाद, अपीलकर्ता ने माना कि पहले प्रतिवादी के पास 9.87 एकड़ जमीन थी। 1 जनवरी, 1970 को सीलिंग सीमा से अधिक भूमि। 5 दिसंबर, 1985 को उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश के खिलाफ दायर नागरिक पुनरीक्षण याचिका पर मामले को अपीलकर्ता को भेज दिया। रिमांड के बाद, अपीलकर्ता ने 12 अगस्त, 1993 के अपने आदेश द्वारा अतिरिक्त भूमि (7.26.040 एकड़) की मात्रा निर्धारित की, जिसे उसके द्वारा आत्मसमर्पण किया जाना था। अपीलकर्ता के उस आदेश के विरुद्ध दो नागरिक पुनरीक्षण याचिकाएँ दायर की गईं - एक घोषणाकर्ता द्वारा और दूसरी उसकी तीन बहनों द्वारा। उच्च न्यायालय ने ऊपर उल्लिखित आक्षेपित निर्णय द्वारा उनका निपटारा कर दिया। वर्तमान अपीलें इसी प्रकार हमारे सामने हैं।

मूल प्रश्न यह है कि क्या घोषणाकर्ता, उसके दो भाई और चार बहनें मृतक एलनजिक्कल सिरिएक द्वारा छोड़ी गई जमीन में हिस्सेदारी की हकदार हैं। प्रश्न का उत्तर ही इस मामले का परिणाम तय करता है. यदि उन सभी को भूमि विरासत में मिली है, तो अपील विफल हो जाएगी, लेकिन यदि यह पाया जाता है कि बहनों को विरासत में नहीं मिली है, तो उनके द्वारा की गई बिक्री अमान्य होगी और अपीलकर्ता को सफल होना होगा, घोषणाकर्ता अतिरिक्त संपत्ति को सरेंडर करने के लिए उत्तरदायी होगा। अपीलार्थी द्वारा धारित भूमि। किसी व्यक्ति की संपत्ति का उत्तराधिकार पूर्ववर्ती राज्य त्रावणकोर, कोचीन में त्रावणकोर ईसाई उत्तराधिकार

अधिनियम, 1992 द्वारा शासित होता था, जो एक पार्ट-बी राज्य था। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम को भाग-बी राज्य (कानून) अधिनियम द्वारा त्रावणकोर कोचीन राज्य तक विस्तारित किया गया था। 1951.परिणामस्वरूप, मृतक सिरिएक के सभी बच्चों को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भूमि विरासत में मिली।इसमें कोई विवाद नहीं है कि यदि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है, तो सभी बहनें मृतक एलनजिक्कल सिरिएक द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों में भाइयों के साथ समान हिस्सेदारी की हकदार होंगी। मैरी रॉय मामले में इस न्यायालय के फैसले से इस स्थिति को मान्यता मिली। और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य (1986] 2 एससीसी 209। इस अदालत ने निर्धारित किया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 को त्रावणकोर कोचीन के भाग-बी राज्य में विस्तारित करने पर, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम इसके बाद खोले गए उत्तराधिकार पर लागू होता है। यह इस प्रकार है कि सभी बहनों की जमीन में हिस्सेदारी थी और इसलिए, बिक्री में शामिल भूमि को घोषणाकर्ता की हिस्सेदारी में नहीं जोड़ा जा सकता था क्योंकि उनके द्वारा निष्पादित विलेख वैध होगा।

इस मामले को ध्यान में रखते हुए, अपीलें विफल हो जाती हैं और उन्हें खारिज कर दिया जाता है, लेकिन मामले की परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना।

आर पी अपील खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।